



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430]

नई दिल्ली, शुक्रवार, 31, 1997/कार्तिक 9, 1919

No. 430]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 1997/KARTIKA 9, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1997

आयकर

सा. का. नि. 632 (अ).—चूंकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और आर्थिक अपवर्चन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और बेल्जियम किंगडम की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित करार उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 29 के पैराग्राफ-1 के अनुसार उक्त करार को लागू करने के लिए दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा अपेक्षित कार्यवाहियों को पूरा करने के बारे में एक दूसरे के लिए जारी की गयी अधिसूचनाओं में से पश्चातवर्ती अधिसूचना के प्राप्त होने के पश्चात् तीसरें दिन अर्थात् अक्टूबर, 1997 के प्रथम दिन को प्रवृत्त हो गया है :

इसलिए अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंध भारत के संघ में लागू किए जाएंगे।

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवर्चन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

बेल्जियम किंगडम की सरकार

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और बेल्जियम किंगडम की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवर्चन को रोकने के लिए एक करार सम्पन्न करने की इच्छा से, नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

अध्याय । - करार का विषय क्षेत्र

अनुच्छेद 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद 2

करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह करार उन सभी करों पर लागू होगा जो चल अथवा अचल सम्पत्ति की विकी, विनियम अथवा अन्तरण से होने वाले लाभों पर लगाए गए करों और उद्यीमियों द्वारा अदा की गयी मजदूरी अथवा वेतनों की कुल राशियों पर लगाए गये करों सहित कुल आय अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए हैं।

"करों" पर में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं होगी जो कि उन करों से संबंधित किसी चूक अथवा गलती के संबंध में देय है जिन पर यह करार लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदण्ड की राशि है ।

2. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार हैं :

१) भारत के मामले में :

११) आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है ; और

१२) अतिकर ;

१३) जिन्हें इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा ।

॥५॥ बेल्जियम के मायले में :

- ॥६॥ व्यष्टि आयकर इल इंपेट डेस पर्सोनेस फिजिक्सः डि पर्सोनेनबेलास्टिंग् ॥;
- ॥७॥ निगमित आयकर इल इंपेट डेस सोसाफीट्सः डि बेनस्चाप्सबेलास्टिंग् ॥;
- ॥८॥ विधिक सत्ताओं पर आयकर इल इंपेट डेस पर्सोनेस मोरल्स; डि रेचर्सपर्सोनेनबेलास्टिंग् ॥;
- ॥९॥ अनिवासियों पर आयकर इल इंपेट डेस नान-रेजिडेंट्स; डि बेलास्टिंग डेर नीट-वरब्लिंग्डर्स् ॥;
- ॥१०॥ व्यष्टि आयकर में सम्मिलित विशेष कर इत्तों कोटिसेशन रैपीशफ्ल एस्समिली प ल इंपेट डेस पर्सोनेस फिजिक्सः डि मेट डे पर्सोनेनबेलास्टिंग गेलिजगेस्टेल्ड बिजजॉडेर हॉफिंग् ॥ ,

जिसमें पूर्व अदायगियां, इन करों और पूर्व अदायगियों पर अधिभार और व्यष्टि आयकर के सम्पूरक शामिल हैं,

॥ जिन्हें इसके बाद "बेल्जियम कर" कहा जाएगा ॥ ।

3. यह करार किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के कर पर भी लागू होगा, जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् विधमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाया जाए । संविवाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, समय-समय पर, अपने-अपने करापानों में किये गये किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को सूचित करेंगे ।

अध्याय ॥ - परिमापां

अनुच्छेद ३

सामान्य परिमापां

1. इस करार में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :

॥१॥ "भारत" पद से अभिप्रेत है भारत का राज्य क्षेत्र तथा उसमें शामिल राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके उनपर का वायुमण्डलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र जिस पर

भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भारत के प्रमुखता-सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों ;

१५६) "बेल्जियम" पद से अभिप्रेत है बेल्जियम किंगडम; जब वह भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त होगा, जिससे अभिप्रेत है राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्रीय समुद्र और कोई अन्य समुद्री क्षेत्र, जिस पर बेल्जियम का, अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रमुखता सम्पन्न अधिकार अथवा क्षेत्राधिकार हों ;

१५७) "संविवाकारी राज्य" और "दूसरे संविवाकारी राज्य" पदों से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा बेल्जियम अभिप्रेत है ;

१५८) "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है :

भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय ऐराजस्व विभाग, अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि और बेल्जियम के मामले में, वित्त मंत्री अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

१५९) "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार "भारतीय कर" अथवा "बेल्जियम कर" अभिप्रेत है ;

१६०) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्याप्ति, कोई कम्पनी और कोई अन्य सत्ता शामिल है, जिसे उस संविवाकारी राज्य में, जिसका वह निवासी है, प्रवृत्त कर कानूनों के अंतर्गत कराये एक रुकाई माना जाता है ;

१६१) भारत के मामले में, "कम्पनी" पद से कोई भी ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जो भारतीय कर-कानून के अंतर्गत कम्पनी है अथवा कम्पनी के रूप में मानी जाती है, और बेल्जियम के मामले में, कोई भी ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जो बेल्जियम कर-कानून के अंतर्गत कम्पनी है अथवा निगमित निकाय के रूप में मानी जाती है ;

१६२) "एक संविवाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविवाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविवाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविवाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

१६३) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविवाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाय

उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;

३०८) "राष्ट्रिक" पद से अभिप्रेत है :

- १) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रियता घारण करने वाला कोई व्यक्ति,
- २) कोई कानूनी व्यक्ति, भागीवारी और संस्था जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से उस रूप में प्राप्त होती हो ।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का, जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो जब तक संर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता है ।

अनुच्छेद ४

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, "किसी संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत, उस राज्य के उन करों के प्रयोजनों के लिए वहां का निवासी हो जिन पर यह करार लागू होता है ।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपर्योगों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उस स्थिति में इस करार के प्रयोजनों के लिए उसके निवास की हैसियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निश्चित की जाएगी :

१) उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं । इस करार में इसके पश्चात् इन्हें उसके "महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र" कहा गया है ।;

२) यदि उस संविदाकारी राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी

संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आवत्तन रहता हो;

१६॥ यदि उसका स्थाई आवास दोनों संविदाकारी राज्यों में है अथवा उसमें से किसी भी राज्य में नहीं है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह एक राष्ट्रिक है;

१७॥ यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रेषन का निर्णय करेंगे ।

३०. जहां व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ १ के उपर्योग के कारण, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध स्थान स्थित है ।

अनुच्छेद ५

स्थायी संस्थापन

१. इस करार के प्रयोजन के लिए, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है ।

२. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

१॥ प्रबंध का कोई स्थान;

२॥ कोई शाखा;

३॥ कोई कार्यालय;

४॥ कोई कारखाना;

५॥ कोई कार्यशाला अथवा कोई भाण्डागार;

६॥ कोई सान, तेल अथवा गैस का कोई कुआं, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;

७॥ कोई प्रतिष्ठापन अथवा संरचना जिसका प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों की सेवा अथवा विदोहन करने के लिए किया जाता हो;

इज़ १ सनिज तेल की खोज करने के लिए अथवा उसे निकालने के लिए अथवा उसके उत्पादन के साथ जुड़ी हुई सेवाओं अथवा सुविधाओं की व्यवस्था करने अथवा उसके लिए प्रयुक्त होने वाले अथवा प्रयुक्त किए जाने वाले किराए के संयंत्र तथा मशीनरी की आपूर्ति;

इज़ २ कोई परिसर जिसका प्रयोग विक्रय-स्थल अथवा खरीद आदेशों को प्राप्त करने अथवा मंगवाने के लिए किया जाता है;

इन्हें कोई भवन स्थल अथवा कोई निर्माण कार्य प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उनसे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप आते हैं, जहां ऐसा भवन-स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप इन्हें ऐसे भवन-स्थलों, परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों, यदि कोई हों, के साथ ३ छः महीने से अधिक की अवधि के लिए चलता रहता है अथवा जहां ऐसी परियोजना अथवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप जो मशीनरी अथवा उपकरण की बिक्री के लिए प्रासंगिक है, कम से कम छः माह से अनधिक अवधि के लिए जारी रहते हैं, परन्तु परियोजना अथवा पर्यवेक्षी कार्यकलाप के लिए अदा करने योग्य प्रमाण मशीनरी और उपकरण के बिक्री मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक है ।

३. "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

१क़ १ किसी उद्यम के माल अथवा फृण्यवस्तुओं के केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग;

१ख़ १ केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा फृण्यवस्तुओं का कोई स्टाक रखना;

१ग १ किसी उद्यम के लिए माल अथवा फृण्यवस्तुओं का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना;

१घ १ उद्यम के लिए केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ।

४. पैराग्राफ ५ के उपर्योगों के अधीन रहते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में, दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में उस उद्यम का स्थायी संस्थापन माना जाएगा, यदि :-

४क॥ वह उस राज्य में, उस उद्यम की ओर से संविदा सम्पन्न करने का प्राधिकार रखता हो और वह अध्यासिक रूप से उस प्राधिकरण का प्रयोग करता हो, जब तक कि उसके कार्यकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पर्यवस्तुओं के क्य तक ही सीमित न हों; अथवा

४ख॥ वह प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में उद्यम के माल अथवा पर्यवस्तुओं का अध्यासिक रूप से ऐसा स्टाक रखता हो, जिसमें से वह व्यक्ति उस उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल अथवा पर्यवस्तुओं की डिलीवरी करता हो; अथवा

४ग॥ वह प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में अनन्यतः अथवा लगभग अनन्यतः उस उद्यम के लिए अथवा उक्त उद्यम और तत्-नियोन्त्रित अन्य उद्यमों के लिए, अथवा उसमें नियंत्रक हित रखने वाले उद्यमों के लिए निरन्तर रूप से आर्डर प्राप्त करता हो ।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेन्ट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेन्ट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । लेकिन, जब ऐसे किसी एजेन्ट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः स्वयं उस उद्यम की ओर से अथवा उस उद्यम और अन्य उद्यमों के लिए किए जाते हों जो उस उद्यम को नियंत्रित करते हों, उस उद्यम द्वारा नियंत्रित हों अथवा उसी तरह के सामान्य नियंत्रण के अधीन हों, तो उसे उस स्थिति में इस प्रैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत एक स्वतंत्र हैसियत का एजेन्ट नहीं समझा जायेगा ।

6. यदि कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में इच्छाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरी कम्पनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जायेगा ।

भव्याय 111 - आय का करायान

अनुच्छेद 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. अचल सम्पत्ति से आय उस संविदाकारी राज्य में करायें हो सकेंगी, जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित हो ।

2. "अचल सम्पत्ति" पद उस संविदाकारी राज्य की विधि के अनुसार परिभ्रषित किया जायेगा, जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है । इस पद में, किसी भी छालत में, ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के उपसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपर्युक्त लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, छोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संधालन के लिए अधिकार कार्य करने के अधिकार के प्रतिपादन के रूप में पीरवर्तनीय अधिकार नियत अवायगियों के अधिकार, ऐसे तथा विमान अचल सम्पत्ति नहीं माने जायेंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपर्युक्त, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग, उसे किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपर्युक्त किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर और व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि यह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुआ माना जा सकता है :— (क) उस स्थायी संस्थापन; (ख) उस दूसरे राज्य में एक-समान अथवा उसी प्रकार के माल अथवा फ्यवस्तुओं की विक्री जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से की जाती है; अथवा (ग) उस दूसरे राज्य में की जाने वाली कारोबार संबंधी वैसी ही अथवा मिलती-जुलती अन्य गतिविधियां जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से की जाती हों ।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां उसको ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण ये लाभ हुए मान जायेंगे, जिनके प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती, जब यह एक-समान या मिलती-जुलती फिरिरहित्ये वा एक-समान या मिलती-जुलती कार्यकलापों में लगा हुआ कोई स्थितंत्र उद्यम होता और जिस उद्यम स्थायी संस्थापन है, उससे निष्पक्ष आधार पर व्यवहार करता हो ।

3. (इ) किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में, उन खर्चों की कटौती की जाएगी जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ सर्व किए जाते हैं तथा जिनमें इस प्रयोग सर्व किए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होते हैं भले ही ये उस राज्य वा सर्व किए गए हों, जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा ये अन्यत्र किये गये हों तथा यह उस राज्य के कर नियमों की सीमाओं के अधीन कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय, जिन के संबंध में अनुमति दी जा सकती है, पर सीमा लगा दी जाए तथा उस सीमा में उस राज्य तथा किसी ऐसे तीसरे राज्य, जो ओ.इ.सी.डी. का सदस्य हो, के बीच किसी ऐसे अधिसमय अथवा करार द्वारा दील दी गई हो अथवा उसे रद्द किया गया हो जो इस करार के प्रवृत्त होने की तारीख के बाद से लागू

होता हो, तो उस राज्य का सक्षम प्राधिकारी तीसरे राज्य के साथ किये गए अभिसमय अथवा करार के लागू होने के तुरंत बाद उस अभिसमय अथवा करार के संगत पेराग्राफ की शर्तों को दूसरे संविवाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा और यदि दूसरे संविवाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसा कोई अनुबोध करे, तो इस उप-पेराग्राफ के उपर्योग को प्रतोकोल द्वारा संशोधित कर दिया जाएगा ताकि ऐसी शर्तों को परिलक्षित किया जा सके ।

इस ॥ परन्तु, स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को, इकास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में ॥, पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायलिट्यों, फिस अथवा अन्य ऐसी ही अदायगियों के रूप में, अथवा विशिष्ट सेवा निष्पादन अथवा प्रबंध के लिए कमीशन के रूप में अथवा अन्य प्रभार अथवा बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर स्थायी संस्थापन को उधार दिये गये धन पर ब्याज के रूप में यदि कोई रकमें अदा की गयी हो तो, उनके संबंध में ऐसी किसी कटौती की स्वीकृति नहीं दी जायेगी । इसी प्रकार, स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उन रकमों को हिसाब में नहीं लिया जायेगा जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को, इकास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में ॥, स्थायी संस्थापन द्वारा पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायलिट्यों, फिसों अथवा अन्य ऐसी ही अदायगियों के रूप में अथवा विशिष्ट सेवा निष्पादन के लिए अथवा प्रबंध के लिए कमीशन के रूप में अथवा, बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, अन्य मामलों में, उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उस के अन्य कार्यालयों में से किसी को उधार दिये गये धन पर ब्याज के रूप में उद्यम के प्रधान कार्यालय अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को प्रभारित की गयी हो ।

4. जहां किसी संविवाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों को उस के विभिन्न अंगों के प्रति अनुभाजन के आधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के माने जाने वाले लाभों को निश्चित करने की प्रथा हो, वहां पेराग्राफ ॥२॥ अथवा पेराग्राफ ॥३॥ की कोई भी व्यवस्था ऐसे संविवाकारी राज्य की ऐसी प्रचलित प्रभाजन पद्धति से, कर सगने वाले लाभों को निश्चित करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी, तथापि, अपनार्ह गई प्रभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के अनुसार होगा ।

5. कोई लाभ, केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जायेगा कि उस स्थायी संस्थापन में, जिस उपर्युक्त का वह स्थायी संस्थापन है, उस उपर्युक्त को निर्यात करने के प्रयोजन से माल अथवा पर्याप्त स्तुति भरी दी जाए।

6. पूर्ववर्ती पैराग्रामी के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्धनुकर्ष उसी पद्धति से निपटायित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं ढूँढ़े जाए।

7. जहाँ आज की भवित्व में लाभों की वे मर्दे कामिल हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है, वहाँ उन अनुच्छेदों के उपर्युक्त इस अनुच्छेद के उपर्युक्तों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

जहाजरानी तथा वायु परिवहन

1. किसी सौविदाकारी राज्य के किसी उपर्युक्त द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रवालन से प्राप्त आय पर दूसरे सौविदाकारी राज्य में कर नहीं लगेगा।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ :

(क) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रवालन से सीधी संबंधित नियियों पर द्व्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के प्रवालन से प्राप्त आय के रूप में माना जाएगा तथा अनुच्छेद 11 के उपर्युक्त ऐसे द्व्याज के मामलों में लागू नहीं होंगे, सद्गुरुसार ऐसी आय पर कोई अवधारण कर नहीं लगाया जाएगा;

४३॥ अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से प्राप्त आय का अर्थ है - पैराग्राफ 1 में निहित किसी उपम द्वारा जलयानों अथवा वायुयानों के मालिकों या पट्टेवारों अथवा शार्टररों द्वारा क्रमशः जलयान अथवा वायुयान द्वारा यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल के परिवहन से प्राप्त आय जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

॥१॥ अन्य उपमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिकी;

॥२॥ ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप;

॥३॥ पूर्णतया सम्भित, चालक सहित तथा भाटक आधार पर मुहैया कराये गए जलयानों अथवा वायुयानों को पट्टे पर देना अथवा साती नाथ भाटक आधार पर देना जहाँ पट्टे पर देना ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित किसी कार्यकलाप के लिए आनुषंगिक है;

४॥ अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों के प्रचालन से प्राप्त आय में वह आय भी शामिल है जो अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पर्यावरणों के परिवहन के संबंध में कन्टेनरों के इंजिनमें कन्टेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर तथा तत्संबंधी साज-सामान भी शामिल हैं॥ इस्तेमाल, रस-रसाय अथवा किराये से प्राप्त आय जहाँ यह आय किसी ऐसे कार्यकलाप से प्राप्त होती है जो ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित किसी कार्यकलाप के लिए आनुषंगिक है ।

३. इस अनुच्छेद के उपर्युक्त किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन पर्यासी में भाग लेने से प्राप्त आय पर भी लागू होगे ।

अनुच्छेद 9

सहयोगी उघम

जहाँ

〔१〕 एक सौविदाकारी राज्य का कोई उघम दूसरे सौविदाकारी राज्य के किसी उघम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा फूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा

〔२〕 ये ही व्यक्ति, एक सौविदाकारी राज्य के किसी उघम और दूसरे सौविदाकारी राज्य के किसी उघम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा फूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं,

और योनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उघमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उघमों के बीच रखी जाती हैं, वहाँ ऐसा कोई भी लभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उघमों में से किसी एक उघम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लभ उस उघम के लम्हों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद 10

लम्हांश

1. एक सौविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी वारा दूसरे सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लम्हांश उस दूसरे राज्य में करायेय होंगे ।

2. तथापि, ऐसे लम्हांशों पर उस सौविदाकारी राज्य में भी, उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, जिसकी लम्हांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता, लम्हांश का हितभोगी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लम्हांश की सकल रकम का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

इस पैराग्राफ का उन लाभों के संबंध में कम्पनी के करापान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है ।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अभिप्राय, शेयरों, "जेयोसेन्स" शेयर अथवा "जेयोसेन्स" राइट्स, लनन-शेयरों, प्रवर्त्तक के शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभ की भागीकारिता के रूप-दावे नहीं हैं और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है, जिस पर वही करापान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है। इस पद का आशय भी आय से है - चाहे उसका भुगतान व्याज के रूप में किया गया हो या शेयर पूँजी वाली कम्पनी से भिन्न किसी ऐसी कम्पनी के सदस्यों द्वारा निवेश की गई पूँजी से प्राप्त हुई हो, जो बेल्जियम कीनिवासी कम्पनी हो ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपर्युक्त उस स्थिति में लागू नहीं होगे, यदि लाभांशों का हितभोगी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार करता है जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी, वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से, निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में, यथास्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपर्युक्त लागू होंगे ।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाते हों अथवा जहां तक कि जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह उस राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबोधित है, वहां उस दूसरे राज्य में कम्पनी के अधितरित लाभों पर अधितरित लाभ संबंधी कर नहीं लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अधितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों ।

अनुच्छेद 11

ब्याज

1. एक सेवियाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे सेवियाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस सेवियाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा, जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, परन्तु यदि ब्याज का हितभोगी स्वामी दूसरे सेवियाकारी राज्य का निवासी हो तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :

[(क)] ब्याज की सकल राशि का 10 प्रतिशत, यदि ऐसा ब्याज किसी बैंक द्वारा मंजूर किये गये किसी प्रकार के किसी ऋण पर अदा किया जाता है; और

[(ख)] सभी अन्य मामलों में ब्याज की सकल राशि का 15 प्रतिशत ।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्ति "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है - प्रत्येक प्रकार के ऋण-संबंधी वायों से प्राप्त आय, जाहे ये बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं हो और जाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और यिहेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हों । तथापि, अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 3 के दूसरे वाक्य के अंतर्गत लाभांश के रूप में भाने गये ब्याज को इस अनुच्छेद के उद्देश्य के सिए "ब्याज" शब्द इसमें शामिल नहीं होगा ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपर्युक्त उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभोगी स्वामी, सेवियाकारी राज्य का निवासी होने से, दूसरे सेवियाकारी राज्य में जिसमें ब्याज उत्पन्न हुआ

हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवायें करता हो और जिस इण्ड-दावे के बारे में व्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्राप्ती रूप से सम्बद्ध हो । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपर्यंथ, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।

5. व्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब व्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो । किन्तु, जहाँ, व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, आहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है, जिसके संबंध में वह इण्ड सिया गया था, जिस पर व्याज की अदायगी ही जाती है, और इस प्रकार का व्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा बहन किया जाता है, तो इस प्रकार का व्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

6. जहाँ, व्याज अदाकर्ता सदा हितमोगी स्थामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई व्याज की रकम, उस इण्ड-दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए व्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितमोगी स्थामी के बीच सहमति हो गई होती, वहाँ इस अनुच्छेद के उपर्यंथ केवल अन्तिम वर्गित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस करार के अन्य उपर्योग का सम्यक अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर सकाया जाएगा ।

अनुच्छेद 12

रायलिट्यों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायलिट्यों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायलिट्यों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हो, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा । लेकिन यदि रायली अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितमोगी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर, रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. [एक] इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायली" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियों के किसी भी कापीराइट के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए, जिनमें सिनेमा-फिल्म, टेलिविजन के संबंध में उपयोग में आने वाली फिल्में अथवा बीड़ियो टेंपे अथवा रेडियो प्रसारण के संबंध में इस्तेमाल के लिए टेंपे भी शामिल हैं, कोई पेटेंट, ट्रेड मार्क, हिजाइन अथवा माडल, प्लान, गुप्त फर्मूला अथवा प्रक्रिया अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी अनिवार्य है ।

[स] इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद में प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्श-वात्री स्वरूप की सेवाओं के लिए, जिनमें तकनीकी सेवाओं अथवा अन्य कार्यकों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, प्रतिफल के रूप में, अदायगियां करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी को की जाने वाली अदायगियों से भिन्न किसी व्यक्ति को की जाने वाली किसी किसी की अदायगियों से और अनुच्छेद 14 में वर्णित स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति की की गई अदायगियों से अनिवार्य है ।

4. पेराग्राफ 1 और 2 के उपर्युक्त उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों का हितभोगी स्थामी, जो एक सौविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे सौविदाकारी राज्य में, जिसमें रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उद्भूत होते हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिकारी सेवाएं करता है, तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क अदा किए जाते हैं, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित हैं। ऐसे मामले में यथास्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपर्युक्त लागू होंगे।

5. एक सौविदाकारी राज्य में रायलिट्यों और तकनीकी सेवाओं के लिए प्रीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब रायलिट्यों और प्रीस अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए प्रीस अदा करने वाले व्यक्ति का चाहे वह किसी सौविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक सौविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए प्रीस अदा करने का वचन विद्या गया हो और ऐसी रायलिट्यों या तकनीकी सेवाओं के लिए प्रीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा बहन की जाती हो, तब ऐसी रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए प्रीस उस सौविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां, अदाकर्ता और हितभोगी स्थामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए प्रीस की रकम, इसके उपयोग, अधिकार तथा सूचना अथवा तकनीकी सेवाओं, जिसके लिए इसकी अदायगी की गई थी, उस रकम से बढ़ जाती है जितनी रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता तथा लभ्यभोगी स्थामी के बीच सहमति हुई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपर्युक्त केवल अन्तिम वर्णन रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, रायलिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए प्रीस के संबंध में अदा की गई रकम का आधिकार भाग प्रत्येक सौविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार करायें होगा।

बनुष्ठेद 13

पूर्णिगत अभिलाभ

1. बनुष्ठेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अबल सम्पर्क के अन्तरण से पक्ष संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. ऐसी अल सम्पर्क के अन्तरण से ज्ञाने वाले अभिलाभों पर, जो पक्ष संविदाकारी राज्य के किसी उपराज की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबाहर-सम्पर्कित कम पक्ष हिस्सा है अथवा किसी निरीक्षण स्थान से संबंधित ऐसी अल-सम्पर्क के अन्तरण से होने वाले अभिलाभों पर, जो सम्पर्कित पक्ष संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोगशार्य उपराज्य हैं, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन इकलौते अथवा पूर्ण उपराज्य के साथ अथवा ऐसे निरीक्षण स्थान के अन्तरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।
3. अन्तरराज्यीय यातायात में अलाप जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के भूमालन से संबंधित अल सम्पर्क के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका कि अन्तरणकर्ता निवासी है।
4. किसी ऐसी कम्पनी के पूर्णिगत स्टाक के वेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जिसकी सम्पर्क प्रयोगशातः अथवा आप्यज्ञातः प्रयोगशातः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अबल सम्पर्क हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
5. किसी ऐसी कम्पनी के, पैराग्राफ 4 में उल्लिखित वेयरों से भिन्न, वेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जो कि कम्पनी के पूर्णिगत स्टाक की कम से कम 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी बनती हो, जो संविदाकारी राज्य की निवासी कम्पनी हो, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
6. पैराग्राफ 1,2,3,4 तथा 5 में उल्लिखित सम्पर्क से भिन्न, किसी भी सम्पर्क के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है।

बन्धुक्ति 14**स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएँ**

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वतृप्त वाले इसी प्रकार के अन्य कार्यकर्ताओं से प्राप्त आय, निम्नस्तिवित परीस्थितियों को छोड़कर, जिनमें जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उस राज्य में करारेय होगी :

इक] यदि उसे अपने कार्यकर्ताओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा, जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

इम] यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियाँ संगत "फिल्से वर्ष" अथवा "करारेय वर्ष" में, कुस मिलाकर 183 विनों अथवा उससे अधिक हों, तो यथास्थिति के अनुसार उस मामले में आय के केवल उतने ही भाग पर, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकर्ताओं से प्राप्त होती हो ।

2. "व्यावसायिक सेवाएँ" एवं स्वतंत्र वैज्ञानिक, सार्वित्यिक, कलात्मक, वैक्तिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकर्ताप तथा विकिसकों, शास्त्र-विकिसकों, वकीलों, रंजीनियरों, वास्तुविदों, धन्त-विकिसकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकर्ताप भी शामिल हैं ।

अनुच्छेद 15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 17, 18, 19, 20 और 21 के उपर्युक्तों के अधीन रहते हुए, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इस प्रकार के अन्य परिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, वक्तरे कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है तो जो परिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. प्रेराग्राफ 1 के उपर्युक्तों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त परिश्रमिक पर केवल प्रथमोहिलासित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

[(क) प्राप्तकर्ता संगत "पिछले वर्ष" अथवा "करायेय अवधि" के दौरान, जैसा भी मामला हो, ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रहा है जो कुल मिलाकर 183 विनों से अधिक नहीं है;

[(ख) परिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से शुकाया गया है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और

[(ग) ऐसे किसी स्थाई संस्थापन अथवा निश्चित स्थान जो नियोजक का दूसरे राज्य में हो, के सभी अथवा आय की संगणना करने में, परिश्रमिक की कटौती नहीं की जायेगी।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपर्युक्तों के होते हुए भी, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में एक संविदाकारी राज्य के किसी उधम द्वारा संचालित पेत अथवा विमान पर दिये गये नियोजन के संबंध में प्राप्त परिश्रमिक पर कर केवल उसी संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 16**निवेशकों की फीस**

1. निवेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियां जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निवेशक मंडल अथवा ऐसे ही अन्य संगठन के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा। यह उपर्युक्त ऐसे कार्यों के निष्पादन से प्राप्त की गई अदायगियों के संबंध में भी लागू होगा, जो उस संविदाकारी राज्य, जिसकी यह कम्पनी निवासी है, के कानूनों के सहत उन कार्यों के सदृश हों जिनका इस से पूर्व उल्लेख किया गया है।

2. पैरा 1 में उल्लिखित किसी निवेशक द्वारा किसी कम्पनी से अपने विन-प्रतिविन के प्रबंधकीय अथवा तकनीकी स्वरूप के कार्यों के लिए प्राप्त किए गए परिश्रमिक तथा किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कम्पनी के भागीदार के रूप में किए गए किसी व्यक्तिगत कार्यकलाप के कारण प्राप्त परिश्रमिक पर, जो शेयर फूंडी वाली किसी कम्पनी से मिल्न हो तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी हो, अनुच्छेद 15 के पैरा 1 के उपर्युक्तों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा मानो ऐसा परिश्रमिक किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त किया गया हो।

अनुच्छेद 17**मनोरंजनकर्ताओं और खिलाड़ियों द्वारा अर्जित आय**

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपर्युक्तों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अप्तु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपर्युक्तों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 के उपर्यों के होते हुए भी, किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, जो एक सौविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे सौविदाकारी राज्य में उसी हैसियत से किए गए अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से अर्जित आय प्रथमोरिलिसित सौविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी, यदि दूसरे सौविदाकारी राज्य में कार्यकलाप प्रथमोरिलिसित सौविदाकारी राज्य की, जिसमें उसके राजनैतिक उपचाराग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्त समर्थत होते हों।

4. पैराग्राफ 2 तथा अनुच्छेद 7, 14 तथा 15 के उपर्यों के होते हुए भी, जहाँ किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा उसी हैसियत में एक सौविदाकारी राज्य में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय, मनोरंजनकर्ता अथवा स्वयं खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती है, परन्तु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो उस मामले में वह आय केवल दूसरे सौविदाकारी राज्य में ही कर योग्य होगी, यदि वह अन्य व्यक्ति दूसरे सौविदाकारी राज्य का निवासी हो, जिसमें उसके राजनैतिक उपचाराग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल हैं, सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थत किया गया हो।

अनुच्छेद 18

गैर-सरकारी पैशन तथा वार्षिकियां

1. एक सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे सौविदाकारी राज्य के ग्रोलों से प्राप्त अनुच्छेद 19 में उल्लिखित किसी पैशन से भिन्न किसी पैशन अथवा किसी वार्षिकी पर कर केवल प्रथमोरिलिसित सौविदाकारी राज्य में लगेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपर्यों के होते हुए भी, किसी ऐसी सार्वजनिक योजना के अंतर्गत आय की गई पैशनों पर्व अन्य भुगतानों पर, जो किसी सौविदाकारी राज्य की सामाजिक सुरक्षा पद्धति अथवा किसी राजनैतिक उपचाराग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण का भाग है, केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

3. "पैशन" एवं से फिल्ली सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में जथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान हुई क्षतियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में की जाने वाली आवधिक अदायगी अनिवार्य है।

4. "वार्षिकी" एवं से जीवन-काल में अथवा किसी विनिर्दिष्ट या अस्तिनिश्चित समयावधि के दौरान धन-राशि अथवा उसके बराबर मूल्य में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिफल की अदायगी करने के इकार के अंतर्गत आवधिक रूप में निश्चित समय पर अदायगी-योग्य एक निश्चित राशि अनिवार्य है।

अनुच्छेद 19

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेशन

1. **१।** किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्याप्ति को उस राज्य अथवा उसके उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अवा किए गए, पेशन से भिन्न, पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा ।

२। तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्याप्ति उस राज्य का निवासी है, जो :

॥१॥ उस राज्य का एक राष्ट्रिक है, अथवा
 ॥२॥ मात्र सेवाएं पेश करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।

२. **३।** किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सूजित कोष द्वारा उसमें से किसी व्याप्ति को उसके द्वारा उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेशन पर केवल उसी राज्य में लग सकेगा ।

४। लेकिन, ऐसी पेशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर केवल तब लग सकेगा यदि व्याप्ति उस अन्य राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।

३. अनुच्छेद 15, 16 और 18 के उपर्युक्त किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाप गए किसी कारबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेशन पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद 20

अध्यापक और अनुसंधानकर्ता

- कोई व्यक्ति, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो और वह दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था के नियंत्रण पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था में अध्यापन करने अथवा अनुसंधान करने अथवा दोनों मुख्य प्रयोजनों से जाता है, तो उस व्यक्ति को, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में पहुंचने की तारीख से ऐसी अवधि के लिए जो 24 महीने से अधिक नहीं हो, ऐसे अध्यापन अथवा अनुसंधान के लिए वैयक्तिक सेवाओं से होने वाली आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य के द्वारा कर नहीं लगाया जाएगा।
- यदि ऐसा अनुसंधान मुख्यतः किसी विशेष व्यष्टि अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है तो उस अनुसंधान के लिए की गयी व्यक्तिगत सेवाओं से प्राप्त आय के संबंध में यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा।
- इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 21 के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यष्टि को एक संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, यदि जिस वर्ष में वह दूसरे संविदाकारी राज्य में जाता है, उस वर्ष में, अथवा उस वर्ष के तत्काल पूर्वीर्ती वर्ष में, वह उस पूर्वोक्त संविदाकारी राज्य का निवासी रहा है।

अनुच्छेद 21

विद्यार्थीयों और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त अदायगियां

- जो व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो और दूसरे संविदाकारी राज्य में अनन्यतः :-
 - उस दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था में विद्यार्थी के रूप में; अथवा
 - व्यावसायिक प्रशिक्षु के रूप में; अथवा
 - अध्ययन अथवा अनुसंधान के प्रयोजन के लिए, किसी सरकारी, धार्मिक, सैराती, वैज्ञानिक अथवा शैक्षणिक संगठन से अनुदान, भत्ता अथवा पुरस्कार पाने वाले के रूप में रहता है, उसे उस दूसरे संविदाकारी राज्य में :-
 - उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए विदेश से प्रेषित सब रकमों के संबंध में;
 - अनुदान, भत्ते अथवा पुरस्कार के संबंध में; और

¶¶¶¶ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में नियोजन के लिए पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त रकम के संबंध में, यदि ऐसा पारिश्रमिक किसी भी वर्ष में, यथास्थिति, बेल्जियम के 1,00,000 फ्रांक अथवा भारतीय रूपयों में उसके समतुल्य रकम से अधिक नहीं हो तो, उस पर कर से छूट प्राप्त रहेगी ।

2. जो व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम अथवा पैराग्राफ 1 में उल्लिखित किसी संगठन के कर्मचारी के रूप में अथवा उसके साथ अनुबंध के अधीन ऐसे उद्यम अथवा संगठन से भिन्न किसी व्यक्ति से तकनीकी, व्यावसायिक अथवा कारोबार संबंधी अनुभव अर्जित करने के मूल प्रयोजन से दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी अवधि के लिए, जो एक वर्ष से अधिक नहीं है, जाता है तो, वह व्यक्ति उक्त अवधि के लिए, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस उद्यम अथवा संगठन से प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में, यदि ऐसा पारिश्रमिक किसी वर्ष में 1,20,000 बेल्जियम फ्रांक अथवा भारतीय रूपयों में उसके समतुल्य रकम से अधिक नहीं हो, जैसा भी मामला हो, तो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से मुक्त रहेगा ।

अनुच्छेद 22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मर्दे, जहां-कहीं थे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में करारेय होंगी ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथापरिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है, तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति, जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्राप्ती रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मर्दे पर भी, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं, उस दूसरे राज्य में भी कर लगेगा ।

अध्याय IV - दोहरे कराधान के अपकरण के लिए पद्धतियां

अनुच्छेद 23

दोहरे कराधान का अपकरण

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रवृत्त कानून, संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के निर्धारण और कराधान के मामलों में लागू होनी विवाय ऐसे मामलों को छोड़कर जहां पर इस करार में उनके विपरीत कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है ।
2. भारत के मामले में, निम्न प्रकार से दोहरे कराधान से बचा जाएगा :
 (१) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार बेल्जियम में कर लगेगा, वहां भारत, वहां प्रत्यक्ष रूप से अध्याक्ष कटौती के द्वारा उस निवासी की आय पर, बेल्जियम में अदा की गयी आयकर की रकम के बराबर की रकम पर कर से कटौती की अनुमति देगा । तथापि, ऐसी कटौती की रकम, आयकर और कटौती दिप जाने से पूर्व यथासंगणित के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो कि ऐसी आय के कारण हो जिस पर बेल्जियम में कर लगाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, जहां ऐसा निवासी कोई कम्पनी है जिस के द्वारा भारत में अतिकर संदेय है, वहां बेल्जियम में अदा किए गए आयकर के संबंध में कटौती प्रत्यमतः कम्पनी द्वारा भारत में संदेय आयकर में से अनुमत्य होगी तथा शेष रकम यदि कोई हो, उसके द्वारा भारत में संदेय अतिकर में से अनुमत्य होगी ।
 (२) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार केवल बेल्जियम में कर लगेगा, वहां भारत इस आय को कर-आधार में शामिल कर सकता है, परन्तु आयकर के उस भाग को, जो बेल्जियम से प्राप्त की गयी आय के कारण बनता है, आयकर से कटौती के रूप में अनुमति देगा ।
3. बेल्जियम के मामले में, निम्न प्रकार से दोहरे कराधान से बचा जाएगा :
 (१) जहां बेल्जियम का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 2, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2 और 6 और अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2 और 6 से भिन्न, इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगेगा, वहां बेल्जियम ऐसी आय को कर से छूट देगा लेकिन उस निवासी की शेष आय पर कर की रकम की संगणना करने में कर की वह दर लागू कर सकेगा जो यदि ऐसी आय को छूट न प्रदान की गई होती, लागू होती ।

४४। यहां बेल्जियम का कोई निवासी बेल्जियम कर प्रयोजनों के लिए अपनी कुल आय की मद्देन प्राप्त करता है, जो कि अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 2 के अनुसार कराधेय लम्बांश हैं और जो उप-पैरा ४ग ३ के अनुसार बेल्जियम कर, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2 अथवा 6 के अनुसार कराधेय व्याज अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2 अथवा 6 के अनुसार कराधेय रायहिट्यों से कर मुक्त नहीं है, वहां उस आय पर लगाये गये भारतीय कर को विदेशों में अदा किए गए करों के बेल्जियम कर से कटौती के बारे में बेल्जियम के कानूनों के मौजूदा उपर्युक्तों के अनुसार ऐसी आय के संबंध में बेल्जियम के कर के प्रति क्रेडिट के रूप में अनुमति दी जाएगी।

४५। यहां बेल्जियम का कोई निवासी तकनीकी सेवाओं के लिए फीसें प्राप्त करता है जिन पर अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2 अथवा 6 के अनुसार भारत में कर लगाया गया है, वहां बेल्जियम से बाहर के द्वारा द्वारा इसे अदा किए गए लम्बांशों पर, जिन पर अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 2 के अनुसार भारत में कर लगेगा, बेल्जियम के कानून में दी गई शर्तों तथा सीमाओं के अंतर्गत बेल्जियम में निर्गमित आयकर से छूट दी जाएगी।

४६। यहां बेल्जियम के कानून के अनुसार भारत में स्थित किसी स्थायी संस्थापन में बेल्जियम के किसी निवासी द्वारा संचालित किसी उद्यम को हुप घाटे को, बेल्जियम में उसके कराधान के लिए उस उद्यम के लाभों से प्रभावशाली रूप से घटा दिया जाएगा, वहां उप-पैराग्राफ ४क ३ में दी गई छूट उस संस्थापन के कारण अन्य कराधेय अवधियों के लाभों के लिए बेल्जियम में उस सीमा तक लागू नहीं होगी जिस सीमा तक उन लाभों को भारत में भी उक्त घाटों की प्रतिपूर्ति के कारण कर से छूट दी गई है।

४७। उप-पैराग्राफ ४स ४।।। के प्रयोजनों के लिए "लगाये गये भारतीय कर" पद में कोई ऐसी रकम शामिल नहीं जाएगी जो भारत के कानूनों के अंतर्गत और इस करार के उपर्युक्तों के अनुसार किसी वर्ष के संबंध में भारतीय कर के रूप में संवेद्य होती, अगर नेप्पनलिंगित के अंतर्गत उस वर्ष के लिए कराधेय आय की संगणना करने में

अनुमत्य कोई कटौती अथवा कोई छूट अथवा कर की कोई कटौती मंजूर न की गई होती :

१। आयकर अधिनियम, 1961 §1961 का 43॥ की धारा 10॥4॥, 10॥4॥, 10॥15॥, १८॥ तथा ८०ठ, जहां तक वे इस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख को लागू थीं और जो अब तक संशोधित नहीं की गई हैं, अथवा केवल इतने मामूली अंश में संशोधित की गई हैं जिससे कि उनका सामान्य स्वरूप प्रभावित न हो, अथवा

२। कोई ऐसा अन्य उपर्युक्त, जिसे करार के लागू होने के बाद अधिनियमित किया गया हो और जिसके अधीन कराधेय आय की संगणना में कोई कटौती अथवा कर से कोई छूट अथवा घटौती प्रदान की गई हो और जिसके लिए संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी भारत के आर्थिक विकास के प्रयोजनों के लिए सहमत हो गए हों, वर्तमान के उसके बाद संशोधित नहीं किया गया हो अथवा केवल इतने मामूली अंश तक ही संशोधित किया गया हो जिससे कि इसका सामान्य स्वरूप प्रभावित न हुआ हो, तो ऐसे किसी मामले में सक्षम प्राधिकारी उस अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं जिसके लिए इस खण्ड का लाभ उपलब्ध होगा ।

अध्याय V - विवेष उपर्युक्त

अनुच्छेद 24

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिक पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं को लागू नहीं किया जाएगा, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों को कैसी ही पीरिस्थितियों में और कैसे ही उपर्युक्तों के अधीन लगाए जाने वाले कराधान एवं तत्संबंधी अपेक्षाओं से मिन्न एवं अपेक्षाकृत अधिक भारपूर हों । यह उपर्युक्त, अनुच्छेद 1 के उपर्युक्तों के होते हुए भी, उन व्यक्तियों पर भी लागू होंगे जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं ।

2. अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपर्युक्तों के अध्यधीन, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन को, उस दूसरे राज्य में, ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा

जो उस दूसरे राज्य के, वैसी ही परिस्थितियों में और उपर्युक्तों के अधीन वैसे ही कार्य में संलग्न उधम को लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो ।

3. पेराग्राफ 2 के उपर्युक्तों का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि :-

१क। इससे दूसरे सौविदाकारी राज्य के किसी उधम के प्रथमोहिलित राज्य में रिति किसी स्थायी संस्थापन के लाभों पर, कर की ऐसी वर लगाने से रोकना है जो कि उस वर से अधिक है जो प्रथमोहिलित सौविदाकारी राज्य के उसी प्रकार के लाभों पर लगाई जाती है;

२ख। बैलिज्यम में किसी ऐसी कम्पनी के, जो भारत की निवासी है, किसी स्थायी संस्थापन को अदा किए गए लाभांशों पर अचल सम्पत्ति की पूर्व-अदायगी लागू करने से रोकना है ।

4. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक सौविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह उन व्यक्तियों को, जो राज्य के निवासी नहीं हैं, कर प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियां मंजूर करे, जो कि कानून वारा ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध हैं जो वहां के निवासी हैं ।

5. एक सौविदाकारी राज्य के उधम पर, जिनकी पूँजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे सौविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्थानित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त सौविदाकारी राज्य में वैसी ही परिस्थितियों और वैसी ही शर्तों के अधीन ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से तथा तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर है, जो प्रथमोहिलित राज्य के अन्य समरूप उधमों पर लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती है।

6. इस अनुच्छेद में, "कराधान" पर से अभिप्राय, इस करार में यथाविनिर्विष्ट प्रत्येक किसम के करों से है ।

अनुच्छेद 25

परस्परिक करार कार्यवाही

- जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों सेविदाकारी राज्यों के कारण उस पर इस प्रकार का कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो कि इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है तो वह, उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बावजूद भी, उस सेविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह उस सेविदाकारी राज्य को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है । यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना के दो वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है ।
- यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से, जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे सेविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । बशर्ते कि यह मामला पैराग्राफ 1 में विनिर्विष्ट समय-अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो, किए गए किसी भी समझौते को कायान्वित किया जाएगा चाहे सेविदाकारी राज्यों के आन्तरिक कानूनों में कोई भी समय-सीमा निर्धारित हो ।
- इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न होने पर सेविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें परस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे ।
- इस करार के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए सेविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । यदि किसी समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से मौतिक भर्तों का आदान-प्रदान उपयुक्त हो तो ऐसे आदान-प्रदान सेविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के किसी आयोग के माध्यम से किए जा सकते हैं ।

अनुच्छेद 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. सौंधिवाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपर्यों अथवा सौंधिवाकारी राज्यों के उन कों से संबंधित आन्तरिक कानूनों के उपर्यों को कार्यान्वयित करने के लिए आवश्यक हैं, जो इस करार के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन करापान व्यवस्था करार के प्रतिकूल नहीं हो ताकि विशेष रूप से ऐसे करों की घोसा-घड़ी अथवा अपवंचन को रोका जा सके।

सूचना का आदान-प्रदान करना अनुच्छेद 1 के द्वारा प्रतिबोधित नहीं है। किसी भी सौंधिवाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के आन्तरिक कानून के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है। तथापि, यदि सूचना भेजने वाले राज्य में सूचना को मूलतः गुप्त समझा जाता है तो उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं। प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण करने अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्त्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से सम्बद्ध हो, जिन पर यह करार लागू होता है, ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजन के लिए ही करेंगे परन्तु वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी विद्यार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शर्तों, पदीतियों को और तकनीकों को विकसित करेंगे जिनके बारे में सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा, जिनमें जहां-कहीं उपयुक्त हो, कर अपवंचन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

2. सूचना का आदान-प्रदान या तो किसी नेमी आधार पर स्वतः किया जा सकता है अथवा मामले विशेष अथवा दोनों के संदर्भ में अनुरोध करने पर किया जा सकता है। सौंधिवाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उस सूचना की सूची पर समय-समय पर सहमत होंगे जो किसी नेमी आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपर्यों का अर्थ किसी सौंधिवाकारी राज्य पर निम्नलिखित वायित्व डालना नहीं होगा :—

१क॥ उस अथवा दूसरे सौंधिवाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;

४३४१ ऐसी सूचना की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे सौंधिवाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं हैं;

४३४२ ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गुप्त अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो अथवा ऐसी सूचना जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के ग्रातंकूल है ।

अनुच्छेद 27

वसूली में सहायता एवं सहयोग

1. सौंधिवाकारी राज्य एक-दूसरे को सहायता एवं सहयोग देंगे ताकि अनुच्छेद 2 में उल्लिखित करों को अधिसूचित और वसूल किया जा सके ।

2. करों की अदायगी में देरी अथवा चूक करने के कारण संदेय ब्याज को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ कर समझा जाएगा ।

3. किसी सौंधिवाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, अन्य सौंधिवाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी, कानूनी उपबंधों के अनुसार तथा अधिसूचना के संबंध में लागू नियमों के अनुसार अपने उन करों की वसूली करेगा, जिसका उल्लेख अधिसूचना तथा करों की वसूली के लिए उनपर उल्लिखित पैरा 1 में किया गया है तथा जो प्रथमोल्लिखित राज्य में देय हैं । जिस राज्य को अनुरोध किया गया है, उस राज्य में ऐसे करों को अधिमान्य दावों के रूप में नहीं समझा जाएगा तथा वह राज्य प्रवर्तन के कोई ऐसे तरीके लागू करने के लिए आव्यय नहीं होगा जो अनुरोधकर्ता राज्य के कानूनी उपबंधों तथा विनियमों वारा प्राधिकृत न हों ।

4. किसी कर के दावे की किसी सीमा अवधि से संबंधित प्रश्न, पैराग्राफ 3 के उपबंधों के होते हुए भी, केवल आवेदक राज्य के कानूनों द्वारा ही शासित होंगे ।

5. पैरा 3 में उल्लिखित अनुरोध-वस्तावेज की एक शासकीय प्रति वारा समर्पित होंगे जिसके द्वारा उसके निष्पादन की अनुमति दी गई हो तथा जहां-कहां भी उचित हो इसके साथ किसी अन्तिम प्रशासनिक अथवा न्यायिक निर्णय की एक शासकीय प्रति संलग्न हो ।

6. ऐसे करों के संबंध में, जिनके बारे में अपील की जा सकती है, एक सौंधिवाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए दूसरे सौंधिवाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को ऐसे सुरक्षोपाय करने का अनुरोध कर सकता है जिनकी उस अन्य राज्य के विधान में व्यवस्था हो; पैरा 1 से पैरा 4 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे उपायों पर लागू होंगे ।

7. यह संविदाकारी राज्य, जिसमें पूर्ववर्ती पैराग्रामों के अनुसरण में कर की वसूली की जाती है, इसके तुरन्त बाद, इस प्रकार वसूल किया गया कर दूसरे संविदाकारी राज्य को लौटाएगा ।

8. अनुच्छेद 26 के पैरा 1 के उपर्युक्त किसी ऐसी सूचना पर भी लागू होंगे, जो इस अनुच्छेद के कारण एक संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को सप्लाई की जाती है ।

अनुच्छेद 28

राजनीयिक तथा कांसुली अधिकारी

इस करार की किसी भी बात से राजनीयिक अथवा कांसुली अधिकारियों को अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपर्युक्तों के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अध्याय VI ~ अन्तिम उपर्युक्त

अनुच्छेद 29

प्रबंधन

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपनी विधि के अंतर्गत अपेक्षित कार्यवाहियों के पूरा कर लिए जाने के बारे में लिखित रूप में राजनीयिक माध्यमों से दूसरे राज्य को अधिसूचित करेगा । यह करार इन अधिसूचनाओं में से बाद में जारी की गई अधिसूचना के प्राप्त होने के बाद तीसवें विन को लागू होगा और इसका निम्नलिखित प्रभाव होगा :-

१क१ भारत में :

जिस कैलेण्डर वर्ष में करार लागू होता है उसके अनुवर्ती वर्ष के अग्रल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी पूर्व वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में;

१ख१ बैंग्जियम में :

१११ जिस कैलेण्डर वर्ष में करार लागू होता है, उस कैलेण्डर वर्ष के बाद आने वाले वर्ष के जनवरी माह की पहली तारीख को अथवा उसके बाद क्रेडिट की गई अथवा संवेद्य आय पर स्रोत पर देय सभी करों के संबंध में;

iii) इंजिस कैलेण्डर वर्ष में करार लागू होता है, उसके बाद आने वाले कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह के अक्तीसवें दिन को अथवा इसके बाद की अवधि में प्राप्त की गई अवधि में देय स्रोत कर को छोड़कर अन्य सभी करों के संबंध में ।

2. आय पर करों के संबंध में दोहरे करापान के परिणाम और राजस्व अपवंशन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा बैलिंगम की सरकार के बीच 7 फरवरी 1974 को हस्ताक्षरित करार तथा उससे संबंधित प्रेतोकोल और 20 अक्टूबर, 1984 को हस्ताक्षरित अनुप्रूपक प्रेतोकोल, जिसके द्वारा उक्त करार तथा प्रेतोकोल का संशोधन किया गया था, समाप्त हो जाएंगे और ऐसी आय पर करों के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएंगे जिनके संबंध में इस अनुच्छेद के पैरा 1 के उपर्योग के अनुसार मौजूदा करार लागू होता है ।

अनुच्छेद 30

समापन

यह कैलार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा । तथापि, दोनों में से कोई भी एक संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने से पांच वर्ष की अवधि के पूरा हो जाने के बाद आरम्भ होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष के जून माह की तीस तारीख को अथवा इसके बाद राजनियक माल्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य को करार के समापन की लिखित तौर पर सूचना दे सकता है तथा ऐसी परिस्थिति में यह करार निम्नलिखित के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

११) भारत में :

जिस कैलेण्डर वर्ष में करार के समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुकर्त्ता वर्ष के औल माह के पहले दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में;

३५४ ऐलिजयम में :

॥१॥ जिस कैलेण्डर वर्ष में करार के समापन की सूचना दी जाती है उसके अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन अथवा उसके बाद कैडिट की गई अथवा संदेय आय पर देय सभी स्रोत करों के संबंध में;

॥२॥ जिस कैलेण्डर वर्ष में करार के समापन की सूचना दी गई है उसके अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह की इकतीस तारीख को अथवा इसके बाद समाप्त होने वाली किसी करायेय अवधि के दौरान प्राप्त की गई आय पर स्रोत पर देय कर के अलावा सभी करों के संबंध में ।

जिसके साक्षय में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राप्तिकृत अपोहस्ताक्षारियों ने इस करार पर हरताक्षर फ़िए हैं ।

—१९७१— में वर्ष एक हजार नौ सौ त्रिशाशुनी के अक्टूबर माह के २६-२७ दिनें हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रेंच तथा डच भाषा में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया तथा चारों गूल पाठ रागान रूप में प्रागार्थिक हैं । अधिभृण में भान्नता की रिखोत में, अंग्रेजी पाठ को प्रागार्थिक गाना जाएगा ।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से
अर्जुन के सेनगुप्ता
राजदूत

ऐलिजयम किंगडम की
सरकार की ओर से
डब्ल्यू. ब्लेस
विदेश मंत्री

प्रतोक्षेत

भारत गणराज्य की सरकार और बैलिजयम फिंगडम की सरकार के बीच, चूंकि आय पर करों के संबंध में दोहरे करापान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक करार निर्धार्ण हुआ है,

इसलिए, दोनों देश उक्त करार पर हस्ताक्षर करते समय निम्नलिखित उपर्योग पर सहमत हो गए हैं जो इसके अधिन्न अंग होंगे :

1. अनुच्छेद 5, 7 और 12

भारत तथा किसी ऐसे तीसरे देश, जो ओ.ई.सी.डी. का सदस्य हो, के बीच कोई ऐसा अभिसमय अथवा करार किया गया हो जो 1 जनवरी 1990 के बाद लागू होता हो, तो यदि भारत ने उनके अंतर्गत रायर्टियो अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर अपने करापान की वर अथवा उसके कार्यक्षेत्र को आय की उक्त मदों के संबंध में मौजूदा करार में दी गई दर की तुलना में अपेक्षाकृत कम निर्धारित की है अथवा इसमें दिए गए कार्यक्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत सीमित कार्यक्षेत्र निर्धारित किया है, तो उक्त आय की मदों के संबंध में उक्त अभिसमय अथवा करार में यथानिर्धारित दर अथवा कार्यक्षेत्र मौजूदा करार के अंतर्गत भी उस तारीख से लागू होगे जिस तारीख से मौजूदा करार अथवा उक्त अभिसमय अथवा करार, इनमें से जो भी बाद वाली तारीख हो, प्रभावी हुआ हो ।

2. अनुच्छेद 7

इक ॥ बैलिजयम में किसी ऐसे उद्यम के स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में जो भारत का निवासी है, बैलिजयम, अनुच्छेद 7 के पैरा 3 के उप पैरा इक ॥ के पहले वाक्य के उपर्योग के होते हुए उन्हीं खर्चों की कटौतियों की अनुमति देगा जो कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय के स्वरूप के हो चाहे वे बैलिजयम में किए गए हों अथवा अन्यत्र जहाँ तक कि वे समुचित रूप से उस स्थायी संस्थापन के लिए अनुमत्य हो;

ख १ जिस सैविवाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन स्थित है यदि उसके कानून के अंतर्गत अनुच्छेद 7 के पैरा 3 के उप पैरा १क० के पहले वाक्य के उपबंधों के अनुसार उन कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक सचर्चों की सीमा निर्धारित की जाती है जिनकी ऐसे स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करते समय कठोरी की अनुमति दी जा सकती है, तो यह समझा जाएगा कि ऐसे स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करते समय ऐसे कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक सचर्चों की राशि किसी भी स्थिति में उस राशि से कम नहीं होगी जो उस सैविवाकारी राज्य के कानून के तहत मौजूदा करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख को अनुमत्य है ।

३० अनुच्छेद 23

पैरा 2 के उप पैरा १क० तथा अनुच्छेद 23 के पैरा 3 के उप पैरा १क० के प्रयोजनार्थ, यह मान लिया जाएगा कि यदि करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बाद सैविवाकारी राज्य के कानून में कर केंडिट करने अथवा कर की कठोरी के संबंध में संशोधन किया जाता है, तो उस सैविवाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार किए गए संशोधनों की दूसरे सैविवाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को सूचना देगा और यदि दूसरे सैविवाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार का अनुरोध करे, तो वोनों ही राज्यों के सक्षम प्राधिकारी करार का संशोधन करने के विचार से आवश्यक होने पर, फ्र०-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

जिसके साथ में, इसके लिए विधिवत् रूप से प्राप्तिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने मौजूदा प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

शुसैल्स में वर्ष एक हजार नौ सौ त्रियानवें के अप्रैल माह के 26वें दिन हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रेंच तथा डच भाषा में दो-दो प्रतियों में निष्पत्ति किया गया तथा आरों मूल पाठ समान रूप में प्रामाणिक हैं । अधीनिरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ को प्रामाणिक माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की

बेल्जियम किंगडम की

सरकार की ओर से

सरकार की ओर से

अर्जुन के. सेनगुप्ता

डब्ल्यू. क्लेस

राजदूत

विदेश मंत्री

[अधिसूचना सं०.10448/97/फा. सं. 505/2/89-वि.क.प्र.]

के. ही. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st, October, 1997

(Income-Tax)

G.S.R. 632 (E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Belgium for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has come into force on the first day of October, 1997, the thirtieth day after the receipt of later of notifications by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required for bringing into force of the said Agreement in accordance with paragraph 1 of Article 29 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

and

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM,

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows:

CHAPTER I

Scope of the agreement

Article 1

Personal scope

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

1. This Agreement shall apply to all taxes imposed on total income or on elements of income including taxes on gains from the sale, exchange or transfer of movable or immovable property and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.

The term « taxes » shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which the Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes.

2. The existing taxes to which the Agreement shall apply are:

(a) In the case of India:

- (i) the income tax including any surcharge thereon; and
- (ii) the surtax,

(hereinafter referred to as « Indian tax »).

(b) In the case of Belgium:

- (i) the individual income tax (l'impôt des personnes physiques; de personenbelasting);
- (ii) the corporate income tax (l'impôt des sociétés; de venootschapsbelasting);
- (iii) the income tax on legal entities (l'impôt des personnes morales; de rechtspersonenbelasting);
- (iv) the income tax on non-residents (l'impôt des non-résidents; de belasting der niet-verblijfshouders);
- (v) the special levy assimilated to the individual income tax (la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques; de met de personenbelasting gelijkgestelde bijzondere heffing),

including the prepayments, the surcharges on these taxes and prepayments, and the supplements to the individual income tax,

(hereinafter referred to as « Belgian tax »).

3. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar tax which is imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall, from time to time, notify to each other any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

Definitions

Article 3

General definitions

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires:

- (a) the term « India » means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law;
- (b) the term « Belgium » means the Kingdom of Belgium; when used in a geographical sense, it means the national territory, the territorial sea and any other area in the sea within which Belgium, in accordance with international law, exercises sovereign rights or its jurisdiction;
- (c) the terms « a Contracting State » and « the other Contracting State » mean India or Belgium as the context requires;
- (d) the term « competent authority » means:
 - in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative, and
 - in the case of Belgium, the Minister of Finance or his authorised representative;
- (e) the term « tax » means « Indian tax » or « Belgian tax » as the context requires;
- (f) the term « person » includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the tax laws in force in the Contracting State of which it is a resident;

- (g) the term « company » means in the case of India any entity which is a company or which is treated as a company under the Indian tax law, and in the case of Belgium any entity which is a company or which is treated as a body corporate under the Belgian tax law;
- (h) the terms « enterprise of a Contracting State » and « enterprise of the other Contracting State » mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (i) the term « international traffic » means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (j) the term « national » means:
 - (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
 - (ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Agreement, the term « resident of a Contracting State » means any person who, under the laws of that State, is a resident of that State for the purposes of the taxes of that State to which the Agreement applies.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status for the purposes of the Agreement shall be determined in accordance with the following rules:
 - (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as his « centre of vital interests »);
 - (b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
 - (c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
 - (d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall determine the question by mutual agreement.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5*Permanent establishment*

1. For the purposes of this Agreement, the term «permanent establishment» means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term «permanent establishment» includes especially:
 - (a) a place of management;
 - (b) a branch;
 - (c) an office;
 - (d) a factory;
 - (e) a workshop or a warehouse;
 - (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
 - (g) an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources;
 - (h) the provision of services or facilities in connection with or supply of plant and machinery on hire used or to be used in, the prospecting for, or extraction or production of mineral oils;
 - (i) a premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders;
 - (j) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activities (together with other such sites, projects or activities, if any) continue for a period of more than six months, or where such project or supervisory activity, being incidental to the sale of machinery or equipment, continues for a period not exceeding six months and the charges payable for the project or supervisory activity exceed 10 per cent. of the sale price of the machinery and equipment.
3. The term «permanent establishment» shall not be deemed to include:
 - (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
 - (c) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;
 - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for scientific research, for the enterprise.
4. Subject to the provisions of paragraph 5, a person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned State if:
 - (a) he has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for that enterprise; or
 - (b) he habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which the person regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or
 - (c) he habitually secures orders in the first-mentioned Contracting State, exclusively or almost exclusively, for the enterprise itself, or for the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise itself or on behalf of that enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control, as that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III Taxation of income

Article 6

Income from immovable property

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.
2. The term «immovable property» shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.
2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall be attributed to such permanent establishment the profits which it might be expected to derive if it were an independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing at arm's length with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. (a) In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, subject to the limitations of the taxation laws of that State. Provided that where the law of the State in which the permanent establishment is situated imposes a restriction on the amount of the executive and general administrative expenses which may be allowed, and that restriction is relaxed or overridden by any Convention or Agreement between that State and a third State which is a member of the OECD which enters into force after the date of entry into force of this Agreement, the competent authority of that State shall notify the competent authority of the other Contracting State of the terms of the corresponding paragraph in the Convention or Agreement with that third State immediately after the entry into force of that Convention or Agreement and, if the competent authority of the other Contracting State so requests, the provisions of this subparagraph shall be amended by protocol to reflect such terms.

(b) However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 or paragraph 3 shall preclude such Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the purpose of export to the enterprise of which it is the permanent establishment.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Income derived from the operation of ships or aircraft in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall not be taxed in the other Contracting State.

2. For the purposes of this Article:

(a) interest on funds directly connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such ships or aircraft and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest; accordingly there will be no withholding tax on such income;

- (b) income derived from the operation of ships or aircraft in international traffic shall mean income derived by an enterprise described in paragraph 1 from the transportation by sea or air respectively of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of ships or aircraft including
 - (i) the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises;
 - (ii) any other activity directly connected with such transportation;
 - (iii) the leasing of ships or aircraft on charter fully equipped, manned and supplied, or on a bare boat charter basis where the leasing is incidental to any activity directly connected with such transportation;
- (c) income derived from the operation of ships in international traffic includes income derived from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) in connection with the transportation of goods or merchandise in international traffic, where the income is derived from an activity which is incidental to any activity directly connected with such transportation.

3. The provisions of this Article shall also apply to income from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

Associated enterprises

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 15 per cent. of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term «dividends» as used in this Article means income from shares, «jouissance» shares or «jouissance» rights, ~~mining~~ shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident. This term means also income even paid in the form of interest — derived from capital invested by the members of a company other than a company with share capital, which is a resident of Belgium.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting state, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed:

- (a) 10 per cent. of the gross amount of the interest, if such interest is paid on any loan of whatever kind granted by a bank; and
- (b) 15 per cent. of the gross amount of the interest in all other cases.

3. The term «interest» as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures; however, the term «interest» shall not include for the purpose of this Article interest regarded as dividends under the second sentence of paragraph 3 of Article 10.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment

or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State.

Article 12

Royalties and fees for technical services

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 20 per cent. of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. (a) The term «royalties» as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

(b) The term «fees for technical services» as used in this Article means payments of any kind to any person, other than payments to an employee of the person making the payments and to any individual for independent personal services mentioned in Article 14, in consideration for services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which, or the contract under which, the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to make the payments was incurred and the payments are borne by such permanent establishment or fixed base, then the royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right, information or technical services for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the royalties or fees for technical services shall remain taxable according to the laws of each Contracting State.

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4, forming part of a participation of at least 10 per cent. of the capital stock of a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State:

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant «previous year» or «taxable period», as the case may be; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term « professional services » includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant « previous year » or « taxable period », as the case may be;
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
- (c) the remuneration is not deductible in computing the profits or income of a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16

Directors' fees

1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. This provision shall also apply to payments derived in respect of the discharge of functions which under the laws of the Contracting State of which the company is a resident are treated as functions analogous to those stated hereinbefore.

2. Remuneration derived by a director referred to in paragraph 1 from the company in regard to the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature and remuneration received by a resident of a Contracting State consequent to some personal activity as a partner of a company, other than a company having a share capital which is a resident of the other Contracting State, may be taxed in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 15, as if such remuneration were derived in respect of an employment.

Article 17

Income earned by entertainers and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a Contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political subdivisions or local authorities.
4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and of Articles 7, 14 and 15, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is a resident of that other Contracting State and is supported wholly or substantially from the public funds of that other State, including any of its political subdivisions or local authorities.

Article 18

Non-government pensions and annuities

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 19, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid and other payments made under a public scheme which is part of the social security system of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof shall be taxable only in that State.
3. The term «pension» means a periodic payment made in consideration of past services, or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.
4. The term «annuity» means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 19

Remuneration and pensions in respect of government service

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

- is a national of that State; or
- did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

Teachers and researchers

1. An individual who is a resident of a Contracting State and who, at the invitation of the Government of the other Contracting State or of a university or other recognised educational institution situated in that other Contracting State, visits such other Contracting State for the primary purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university or other recognised educational institution shall not be subject to tax by that other Contracting State on his income from personal services for such teaching or research for a period not exceeding twenty-four months from the date of his arrival in that other Contracting State.

2. This article shall not apply to income from personal services for research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 21, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is a resident of that Contracting State in the year in which he visits the other Contracting State or in the year immediately preceding that year.

Article 21

Payments received by students and apprentices

1. An individual who is a resident of a Contracting State and visits the other Contracting State solely:

- as a student at a university, college or other recognised educational institution in that other Contracting State, or
- as a business apprentice, or
- for the purpose of study or research, as a recipient of a grant, allowance or award, from a governmental, religious, charitable, scientific or educational organisation,

shall be exempt from tax in that other Contracting State:

- on all remittances from abroad for the purposes of maintenance, education or training;
- on the grant, allowance or award; and
- in respect of the amount, representing remuneration for an employment in that other Contracting State, if such remuneration does not exceed 100,000 Belgian Francs or its equivalent in Indian Rupees, as the case may be, in any year.

2. An individual who is a resident of a Contracting State and who visits the other Contracting State for a period not exceeding one year as an employee of, or under contract with, an enterprise of the first-mentioned Contracting State or an organisation referred to in paragraph 1 for the primary purpose of acquiring technical, professional or business experience from a person other than such enterprise or organisation shall be exempt from tax in that other Contracting State in respect of the remuneration received from that enterprise or organisation for such period, if such remuneration does not exceed 120,000 Belgian Francs or its equivalent in Indian Rupees, as the case may be, in any year.

Article 22

Other income

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of the Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

CHAPTER IV

Methods for elimination of double taxation

Article 23

Elimination of double taxation

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the assessment and taxation of income in the respective Contracting States except where express provision to the contrary is made in this Agreement.

2. In the case of India, double taxation shall be avoided as follows:

- (a) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of the Agreement, may be taxed in Belgium, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Belgium whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) which is attributable to the income which may be taxed in Belgium. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the deduction in respect of income tax paid in Belgium shall be allowed in the first instance from income tax payable by the company in India and as to the balance, if any, from surtax payable by it in India.
- (b) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of the Agreement, shall be taxable only in Belgium, India may include this income in the tax base but shall allow as a deduction from the income tax that part of the income tax which is attributable to the income derived from Belgium.

3. In the case of Belgium, double taxation shall be avoided as follows:

- (a) Where a resident of Belgium derives income which may be taxed in India in accordance with the provisions of the Agreement, other than those of paragraph 2 of Article 10, of paragraphs 2 and 6 of Article 11 and of paragraphs 2 and 6 of Article 12, Belgium shall exempt such income from tax but may, in calculating the amount of tax on the remaining income of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if such income had not been exempted.
- (b) (i) Where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are dividends taxable in accordance with paragraph 2 of Article 10, and not exempt from Belgian tax according to sub-paragraph (c), interest taxable in accordance with paragraphs 2 or 6 of Article 11, or royalties taxable in accordance with paragraphs 2 or 6 of Article 12, the Indian tax levied on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income in accordance with the existing provisions of Belgian law regarding the deduction from Belgian tax of taxes paid abroad.
- (ii) Where a resident of Belgium derives fees for technical services which have been taxed in India in accordance with paragraphs 2 or 6 of Article 12, the provisions of Belgian tax law with respect to earned income derived from sources outside Belgium and subject to foreign tax shall apply.
- (c) Where a company which is a resident of Belgium owns shares in a company which is a resident of India, the dividends which are paid to it by the latter company and which may be taxed in India in accordance with paragraph 2 of Article 10, shall be exempt from the corporate income tax in Belgium under the conditions and limits provided for in Belgian law.
- (d) Where in accordance with Belgian law, losses incurred by an enterprise carried on by a resident of Belgium in a permanent establishment situated in India have been effectively deducted from the profits of that enterprise for its taxation in Belgium, the exemption provided for in sub-paragraph (a) shall not apply in Belgium to the profits of other taxable periods attributable to that establishment to the extent that those profits have also been exempted from tax in India by reason of compensation for the said losses.
- (e) For the purposes of sub-paragraph (b)(i) the term « Indian tax levied » shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax under the laws of India and in accordance with the provisions of the Agreement for any year but for a deduction allowed in computing the taxable income or an exemption from or a reduction of tax granted for that year under:
 - (i) sections 10(4), 10(4B), 10(15)(iv) and 80L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), so far as they were in force on, and have not been modified since, the date of the signature of the Agreement, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character; or
 - (ii) any other provision which may be enacted after the Agreement enters into force granting a deduction in computing the taxable income or an exemption from or a reduction of tax and which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purposes of economic development of India, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character; the competent authorities may in such a case decide as to the period for which the benefit of this clause shall apply.

CHAPTER V.

Special provisions

Article 24

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected

requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be taxed. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. Subject to the provisions of paragraph 3 of Article 7, the taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions.

3. The provisions of paragraph 2 shall not be construed as preventing:

- (a) a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which an enterprise of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar enterprise of the first-mentioned Contracting State;
- (b) Belgium from imposing the movable property prepayment on dividends paid to a permanent establishment in Belgium of a company which is a resident of India.

4. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs or reductions for tax purposes which are by law available only to persons who are so resident.

5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirement to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

6. In this Article, the term « taxation » means taxes of every kind as specified in this Agreement.

Article 25

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Provided that the case has been presented within the time period specified in paragraph 1, any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of giving effect to the provisions of the Agreement. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchanges of information shall be made, including, where appropriate, exchanges of information regarding tax avoidance.
2. Information may be exchanged either spontaneously, on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information which shall be furnished on a routine basis.
3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 27

Aid and assistance in recovery

1. The Contracting States shall lend aid and assistance to each other in order to notify and recover the taxes mentioned in Article 2.
2. The interest due for delay or default in the payment of taxes shall be treated as tax for the purposes of this Article.
3. On the request of the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall secure, in accordance with the legal provisions and regulations applicable to the notification and recovery of its taxes, the notification and the recovery of taxes referred to in paragraph 1 which are due in the first-mentioned State. Such taxes shall not be considered as preferential claims in the requested State and that State shall not be obliged to apply any means of enforcement which are not authorised by the legal provisions and regulations of the requesting State.
4. Questions concerning any period of limitation of a tax claim shall, notwithstanding the provisions of paragraph 3, be governed solely by the laws of the applicant State.

5. Requests referred to in paragraph 3 shall be supported by an official copy of the instrument permitting the execution, accompanied where appropriate, by an official copy of any final administrative or judicial decision.

6. With regard to taxes which are open to appeal, the competent authority of a Contracting State may, in order to safeguard its rights, request the competent authority of the other Contracting State to take the protective measures provided for in the legislation of that other State; the provisions of paragraphs 1 to 4 shall apply mutatis mutandis to such measures.

7. The Contracting State in which tax is recovered in pursuance of the preceding paragraphs shall immediately thereafter remit the amount so recovered to the other Contracting State.

8. The provisions of paragraph 1 of Article 26 shall also apply to any information which, by virtue of this Article, is supplied to the competent authority of a Contracting State.

Article 28

Diplomatic and consular officials

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

CHAPTER VI

Final provisions

Article 29

Entry into force

1. The Contracting States shall notify each other in writing through diplomatic channels that the procedures required by their respective laws for the bringing into force of this Agreement have been completed. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect:

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Agreement enters into force;
- (b) in Belgium:
 - (i) in respect of all tax due at source on income credited or payable on or after the first day of January of the calendar year next following the calendar year in which the Agreement enters into force;
 - (ii) in respect of all tax other than tax due at source on income derived during any taxable period ending on or after the thirty-first day of December of the calendar year next following the calendar year in which the Agreement enters into force.

2. The Agreement between the Government of India and the Government of Belgium for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, and the Protocol thereto, signed on 7th February, 1974 and the Supplementary Protocol modifying the said Agreement and Protocol, signed on 20th October, 1984, shall terminate and cease to have effect in respect of the taxes on income to which the present Agreement applies in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article.

Article 30

Termination

This Agreement shall remain in force indefinitely. However, either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, the Agreement shall cease to have effect:

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given;
- (b) in Belgium :
 - (i) in respect of all tax due at source on income credited or payable on or after the first day of January of the calendar year next following the calendar year in which the notice of termination is given;
 - (ii) in respect of all tax other than tax due at source on income derived during any taxable period ending on or after the thirty-first day of December of the calendar year next following the calendar year in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

DONE in duplicate at Brussels this 26th day of April one thousand nine hundred and ninety three, in the Hindi, English, French and Dutch languages, all four texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

*For the Government of the
Republic of India:*

*For the government of the
Kingdom of Belgium:*

ARJUN K. SENGUPTA
Ambassador

W. CLAES
Minister of Foreign Affairs

PROTOCOL

The Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Belgium,
Having entered into an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,
Have agreed, at the time of signing the said Agreement, on the following provisions which shall constitute an integral part thereof:

1. Ad Articles 5, 7 and 12

If under any Convention or Agreement between India and a third State being a member of the OECD which enters into force after 1st January, 1990, India limits its taxation on royalties or fees for technical services to a rate lower or a scope more restricted than the rate or scope provided for in the present Agreement on the said items of income, the same rate or scope as provided for in that Convention or Agreement on the said items of income shall also apply under the present Agreement with effect from the date from which the present Agreement or the said Convention or Agreement is effective, whichever date is later.

2. Ad Article 7

- (a) In the determination of the profits of a permanent establishment in Belgium of an enterprise which is a resident of India, Belgium shall allow as deductions, notwithstanding the provisions of the first sentence of subparagraph (a) of paragraph 3 of Article 7, executive and general administrative expenses incurred whether in Belgium or elsewhere insofar as they are reasonably allocable to that permanent establishment.
- (b) Where the law of the Contracting State in which a permanent establishment is situated imposes in accordance with the provisions of the first sentence of subparagraph (a) of paragraph 3 of Article 7 a restriction on the amount of the executive and general administrative expenses which may be allowed as deductions in determining the profits of such permanent establishment, it is understood that in determining the profits of such permanent establishment the deduction in respect of such executive and general administrative expenses in no case shall be less than what is allowable as on the date of signature of the present Agreement under the law of that Contracting State.

3. Ad Article 23

For the purposes of sub-paragraph (a) of paragraph 2 and subparagraph (b) of paragraph 3 of Article 23, it is understood that if, after the date of signature of the Agreement, the law of a Contracting State is amended with regard to the allowance of tax credit or the reduction of tax, the competent authority of that State shall inform the competent authority of the other Contracting State of the amendments so made and, if the competent authority of that other Contracting State so requests, the competent authorities of both States shall consult each other with a view to amend the Agreement, if necessary.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Protocol.

DONE in duplicate at Brussels this 26th day of April one thousand nine hundred and ninety three, in the Hindi, English, French and Dutch languages, all four texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

*For the Government of the
Republic of India:*

ARJUN K. SENGUPTA
Ambassador

*For the Government of the
Kingdom of Belgium:*

W. CLAES
Minister of Foreign Affairs
[Notification No. 10448/97-F.No. 505/2/89-FTD.]
K.D. GUPTA, Jt. Secy.